Result Mitra Daily Magazine

भारत की आजादी और विभाजन

❖ आजादी की ओर :

- WW-II के दौरान भारत मध्य-पूर्व एशिया के साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश युद्ध रणनीतियों के लिये काफी महत्वपूर्ण था।
- ब्रिटिश संसद ने इस दौरान भारतीय मामलों पर कडा नियंत्रण बनाए रखते हुए भारतीय संसाधनों का प्रयोग युद्ध में किए जाने की मांग की।
- 1940 में विस्टन चर्चिल ब्रिटेन के PM बने, जो कट्टर साम्राज्यवादी थे एवं भारत को किसी भी प्रकार की रियासत देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके युद्ध मंत्रिमंडल में मतभेद था।

❖ क्रिप्स मिशन :

- चर्चिल के युद्ध मंत्रिमंडल में स्टेफोर्ड क्रिप्स भी एक मंत्री थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित वामपंथी विचारधारा के नेता थे।
- स्टेफोर्ड क्रिप्स भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे।
- दरअसल WW-II के दौरान ब्रिटेन दक्षिण-पूर्व एशिया में लगातार पराजित हो रहा था एवं जापानी आक्रमण का खतरा भारत पर मंडरा रहा था।
- ऐसे में ब्रिटेन भारत का समर्थन करना चाहता था और इसी उद्देश्य से मार्च 1942 में स्टेफोर्ड की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया।
- इसके अलावा मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन पर भारत का समर्थन पाने के लिये भी दबाव बनाया।

❖ प्रमुख प्रावधान :

- युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा और भारत किसी बाहरी या घरेलू सत्ता के अधीन नहीं रहेगा।
- युद्ध के बाद संप्रभु भारत संघ बनाया जाएगा, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने के लिये स्वतंत्र होगा।
- युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा बनाया जाएगा।
- जो रियासत/प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहेगा, उसे अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी।
- तब तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर रहेगा और गवर्नर-जनरल का पद यथास्थिति बना रहेगा।
- डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर कांग्रेस ने इसे नहीं स्वीकारा, फलतः यह मिशन विफल रहा और कांग्रेस ने 8 Aug 1942 को भारत छोडो आंदोलन शुरू किया।

Note :- महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को Post-dated Cheque कहा था, जिसमें जवाहर लाल नेहरू ने "दिवालिया होते बैंक" का वाक्यांश जोडा।

❖ ब्रिटेन के रवैये में परिवर्तन :

- WW-II के अंत होते-होते ब्रिटेन की स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया में।
- मित्र राष्ट्रों, विशेषकर USA के दबाव ने ब्रिटेन को उपनिवेशवाद से मोह-त्यागना पडा।
- 1945 तक ब्रिटेन में राजनीतिक दबाव एवं आर्थिक कमजोरी के कारण परिवर्तन का दौर आया।
- 1945 में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई एवं क्लीमेंट एटली PM बने।
- भले ही लेबर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता के लिये इच्छुक थी, लेकिन ऐसा करने के लिये वह जल्दबाजी में नहीं थी।

❖ हिन्दु-मुस्लिम विभाजन एवं पाकिस्तान की मांग :

- भारत-विभाजन का मूल हिन्दु-मुस्लिम विभाजन के गहराने से प्रेरित थी, जो सत्ता-हस्तांतरण के विभिन्न वार्ताओं से स्पष्ट हो चुकी थी।
- 1940 (मार्च) में लाहौर में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें अल्पसंख्यक मुसलमानों को अलग राष्ट्र में परिवर्तित किये जाने की मांग की गई थी।
- इस प्रस्ताव ने मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों के लिये एकमात्र प्रवक्ता के रूप में स्थापित किया और मुस्लिम लीग की मांगें अपराजय होती गई।
- जिला द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकारना, अपने-आप में मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे वरीयता देने का प्रयास था।
- भारत छोडो आंदोलन के दौरान अंग्रेज एवं मुस्लिम लीग में खूब घनिष्ठ संबंध विकसित हुए।

Result Mitra

- विस्टन चर्चिल ने भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिये इस दौर में मुस्लिम लीग का भरपूर समर्थन किया, जिसने विभाजन प्रवृत्ति को और मजबूत किया।
- इन घटनाक्रमों के बावजूद पूर्ण विभाजन की मांग ज्यादा प्रबल नहीं हुई थी, बल्कि मुस्लिम लीग संघीय ढांचे में शामिल होकर अधिक स्वायत्ता प्राप्त करना चाह रहे थे।

❖ राजनीतिक वार्ताओं की विफलता :

- 1940 के दशक में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुई उच्च-स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें से 1944 का राजाजी फॉर्मूला अहम था, जो सी. राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तावित था।
- इस फॉमूले में युद्ध के बाद एक आयोग गठन करने का प्रावधान था, जो मुस्लिम-बहुल इलाके का सीमांकन करता।
- इसके अनुसार सभी वयस्क जनमत संग्रह द्वारा यह निर्धारित करते कि उन्हें पाकिस्तान में शामिल होना है या नहीं।
- जिला ने प्रस्ताव नहीं स्वीकारा, जिस कारण 1944 में गांधी-जिला वार्ता असफल हो गया।
- 1945 के शिमला सम्मेलन, जो लॉर्ड वेवेल द्वारा आयोजित किया गया था, भी विफल रहा।
- भारतीय कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार अनन्य रूप से जिला मुस्लिम लीग को देने की मांग कर रहे थे, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस सिर्फ हिन्दुओं की पार्टी रह जाती।

❖ मुस्लिम लीग एवं जिला का वर्चस्व :

- 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों का समर्थन पाने में पूरा जोर लगा दिया।
- इस दौरान मुस्लिम लीग को जमींदार, अभिजात वर्ग, व्यापारिक समूह एवं धार्मिक नेताओं का पूर्ण समर्थन मिला।
- पाकिस्तान के मांग को राजनीतिक के साथ-साथ उलेमा, पीर एवं मौलवियों का धार्मिक समर्थन भी प्राप्त था।
- इस दौरान जिन्ना का नेतृत्व अधिकारपूर्ण होता गया, जिससे लीग के प्रांतीय शाखाओं पर उसका नियंत्रण स्थापित होता गया।
- जिन्ना ने बंगाल के प्रमुख नेता ए. के. फजलुल हक एवं पंजाब के सर सिकंदर को हाशिए पर डाल दिया, जिसने जिला के वर्चस्वता का विरोध किया था।

❖ चुनावी जीत : विभाजन के लिये जनादेश

- मुस्लिम लीग के जन-समर्थन आंदोलनों की परिणति 1946 के चुनावों में देखने को मिला, जिसे पाकिस्तान के लिये जनमत-संग्रह के रूप में वर्णित किया गया।

- पंजाब एवं बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में लीग के एकतरफा जीत ने इसे मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर दिया।

❖ क्लीमेंट एटली का निर्णय :

- 1946 के अंत तक एटली भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में मन बना चुके थे, जिसके लिये उन्होंने पर्याप्त प्रशासनिक मशीनरी की कमी, लेबर पार्टी के भीतर विरोध, भारतीय सैन्य की संदिग्ध निष्ठा एवं भारत में सैन्य सेवा देने में ब्रिटिश लोगों की अनिच्छा का हवाला दिया।
- संयुक्त राष्ट्र के दबाव ने एटली को आभास करा दिया कि अब भारत को उपनिवेश बनाकर नहीं रखा जा सकता।

❖ कैबिनेट मिशन :

- 24 मार्च 1946 में ए.वी. अलेक्जेंडर, पेथिक लॉरेंस एवं स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत (दिल्ली) पहुँचा।
- इसमें पेथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं ए.वी. अलेक्जेंडर नौवाहन विभाग के प्रमुख थे।
- इस मिशन की अध्यक्षता पेथिक लॉरेंस ने की थी।

❖ प्रमुख प्रावधान :

- भारत एक संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत एवं देशी रियासतें दोनों शामिल होंगे।
- विदेशी, रक्षा एवं संचार मामले को छोडकर सभी मामलों का नियंत्रण केन्द्र सरकार (भारत) के पास होगा।
- इसके तहत सभी प्रांतों का विभाजन Group A, B एवं C में किया गया।
- समूह C में असम एवं बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे।
- इसमे एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव था, जिसमें लगभग 10 लाख पर एक प्रतिनिधि भेजे जाने का प्रावधान था।
- इसके तहत संविधान सभा के लिये 389 सदस्य तय हुए, जिसमें 292 ब्रिटिश-भारतीय प्रांत से, 93 देशी रियासतों से तथा 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से निर्वाचित होने थे।
- कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया।
- मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग अस्वीकार किये जाने से ध्रुवीकरण की रफ्तार और भी तेज हो गई और 16 Aug 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की गई तो देश के कई हिस्सों में दंगे भडक गए, जिसने भारत के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया।

Result Mitra TM

❖ माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन :

- 3 June 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई, जिसमें पंजाब एवं बंगाल विधानसभाओं को विभाजन पर मतदान करने के लिये हिन्दुओं एवं मुसलमानों के अलग-अलग समूहों में मिलना था।
- यदि कोई भी समूह साधारण बहुमत से विभाजन के पक्ष में मतदान करता तो दोनों प्रांतों को विभाजित कर दिया जाता।
- विभाजन की स्थिति में दो डोमिनियन और दो संविधान सभाएं बनाए जाने का प्रावधान था।
- सिंध को निर्णय लेने के लिये स्वतंत्रता दी गई, जबकि उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत एवं बंगाल के सिलहट क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा भाग्य का निर्धारण किए जाने का प्रावधान था।
- माउंटबेटन योजना ने वास्तविक रूप में विभाजन की मांग को स्वीकार लिया था।

❖ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (IIA) :

- 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन योजना के आधार पर IIA को पारित किया, जिसे 18 जुलाई 1947 को सम्राट की स्वीकृति मिली, जो 15 Aug 1947 को लागू हुआ।

❖ प्रावधान :

- दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन/निर्माण का प्रावधान,
- प्रत्येक डोमिनियन में प्रभावी संचालन के लिये एक-एक गवर्नर-जनरल का प्रावधान,
- जब तक संविधान का निर्माण न हो जाए तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सरकार चलाना था।

❖ Important Facts :

- IIA के तहत पाकिस्तान 14 Aug एवं भारत 15 Aug को आजाद हुआ।
- मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर-जनरल बने, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन कुछ दिनों तक भारत के गवर्नर-जनरल बने रहे।
- स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल बनने का सौभाग्य चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को प्राप्त हुआ, जो जून 1948 में इस पद पर आसीन हुए और जनवरी 1950 तक पद पर बने रहे।

Result Mitra